विश्व बैंक के सहयोग से शुरू होगी यूपी एग्रीस परियोजना

योगी बोले–फसलों की उत्पादकता वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए उपयोगी होगी परियोजना

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (यूपी एग्रीस) की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने साथ कृषि आधारित उद्योगों के नए क्लस्टरों का विकास व निर्यात बढ़ाने का प्रयास होगा। मूंगफली, मिर्च और हरी मटर जैसी फसलों के क्राप क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही करीब चार हजार करोड़ की यह परियोजना किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमियों को तकनीकी सहायता व आधारभूत संरचना भी मुहैया कराएगी। यूपी एग्रीस परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के सात जिलों में संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सोमवार को विश्व बैंक के सौजन्य से कृषि परियोजना विषयक प्रस्तुतीकरण किया गया ●सूचना विभाग

21 पूर्वांचल के व बुंदेलखंड के सात जिलों के लिए सरकार की नई पहल

विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 187.70 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के साथ उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है जहां कुल उपलब्ध भूमि के 76 प्रतिशत पर खेती की जाती है। हमारे पास सिंचित भूमि का कवरेज भी 86 प्रतिशत से अधिक है। बीते सात वर्षों में नियोजित प्रयासों से फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब भी बुंदेलखंड, पूर्वांचल तथा विंध्य क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को नौ एग्रो क्लाइमेटिक जोन का लाभ प्राप्त होता रहा है। नई परियोजना में इन क्लाइमेटिक जोन के आधार पर फसल उत्पादन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

जेवर एयरपोर्ट के पास की जाए एक्सपोर्ट हब की स्थापना : मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी व पूर्वी उप्र राज्य की कुल जनसंख्या में 40-40 प्रतिशत की भागीदारी रखते हैं, लेकिन जहां पश्चिमी उप्र का कृषि उत्पादन में 50 प्रतिशत का योगदान है, वहीं पूर्वी उप्र का योगदान मात्र 28 प्रतिशत है। सात प्रतिशत जनसंख्या बुंदेलखंड में निवास करती है, जबकि कृषि उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 5.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाए। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण में महिला समूहों की भागीदारी भी बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत विशिष्ट उत्पादों के सेंटर आफ एक्सीलेंस का विकास, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने और बाजार मानकों के अनुरूप फसल की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

10 लाख किसानों को मिलेगी सहायता

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अब तक हुई वार्ता के अनुसार यह परियोजना छह वर्ष की होगी जिसका सीधा लाभ कृषकों, कृषक समूहों, मत्स्य पालकों और कृषि सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई इकाइयों को होगा। यूपी एग्रीस परियोजना के माध्यम से 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी, जिनमें से 30 प्रतिशत महिला किसान होंगी। इसके अलावा एक लाख से अधिक मछुआ परिवारों को सहायता दी जाएगी। 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी देखने के लिए विदेश भ्रमण भी कराया जाएगा। परियोजना के माध्यम से इन जिलों में प्रति व्यक्ति आय और बैंकों के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होगी।